

[2023] 4 एस. सी. आर 265

बालवंत सिंह

बी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(लेखन याचिका (सीआरएल) 2020 का सं. 261)

03 मई, 2023

[बी. आर. गवई, विक्रम नाथ और संजय करोल, जे. जे.]

भारत का संविधान-कला। 32 , 72 , 161 - दया याचिका

-

याचिकाकर्ता को यू/एस अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था। 120 बी, आई. पी. सी. की धारा 307 और यू/एस। 3 (बी), 4 (बी) और 5 (बी) आर/डब्ल्यूएस। 6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 और मौत की सजा सुनाई गई-मौत

याचिकाकर्ता के संदर्भ की पुष्टि उच्च न्यायालय के याचिकाकर्ता द्वारा की गई थी, न तो उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील को प्राथमिकता दी गई और न ही दया याचिका को प्राथमिकता दी गई-याचिकाकर्ता के लिए दया याचिका को गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा प्राथमिकता दी गई थी।

- याचिकाकर्ता का मामला यह है कि संघ ने कोई कदम नहीं उठाया है

10 वर्ष से अधिक की दया याचिका पर और इसलिए सजा

याचिकाकर्ता पर अधिरोपित मृत्यु को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जाए और इस तरह की याचिका के साथ याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। 32 - आयोजित किया गया: दया याचिका वर्ष 2012 में दायर की गई थी-याचिकाकर्ता की मौत की सजा को कम करने पर विचार करने के प्रस्ताव के बारे में गृह मंत्रालय की तारीख 27.09.2019 की सूचना शुरू की गई थी और सह-अभियुक्तों के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपीलों के निपटारे तक इसे लंबित रखने का निर्णय लिया गया था।

सी. बी. आई. द्वारा-इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 04.12.2020 और 02.05.2022 पर फिर से निर्देश जारी किए गए और उस मामले पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया-इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि एक

दया याचिका के निपटारे में अत्यधिक देरी-गृह मंत्रालय, अपनी विभिन्न शाखाओं से विभिन्न रिपोर्टों पर भौतिक रूप से विचार करने पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विचार को स्थगित किया जा सकता है क्योंकि इससे राष्ट्र की सुरक्षा से समझौता हो सकता है या कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है-इसलिए,

वर्तमान में कोई भी निर्णय लेने को स्थगित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर विचार करना सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है-यह निर्णय लेना कार्यपालिका के भीतर है।

[2023] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रिट याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. यह भी स्पष्ट है कि के बारे में तर्क

दया याचिका की लंबितता और 10 वर्ष से अधिक की देरी को कायम नहीं रखा जा सकता है। सबसे पहले, याचिकाकर्ता ने खुद कभी कोई दया याचिका दायर नहीं की। कथित दया याचिका

वर्ष 2012 का एस. जी. पी. सी. द्वारा दाखिल किया गया था। इसके अलावा, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 1 के संचार के बाद, याचिकाकर्ता की मौत की सजा को कम करने पर विचार करने का प्रस्ताव शुरू किया गया था और सह-अभियुक्त के साथ-साथ सी. बी. आई. द्वारा दायर इस अदालत के समक्ष लंबित अपीलों के निपटारे तक इसे लंबित रखने का निर्णय लिया गया था, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी के अनुसार, इसका असर होगा और यह हो सकता है

परिवर्तन के उक्त प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक। इसके अलावा, इस न्यायालय द्वारा 04.12.2020 और 02.05.2022 पर जारी निर्देशों के बाद इस मामले पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा फिर से विचार किया गया और गृह मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे में दिए गए कारणों को देखते हुए परिवर्तन के प्रश्न को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। अतः यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि दया याचिका के निपटारे में अत्यधिक देरी हुई है। [पैरा 17] [277-एच; 278-ए-सी] 2. पक्षों के वकील द्वारा तर्क दिए गए किसी भी आगे के मुद्दों में गए बिना, यह पाया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए हैं

याचिकाकर्ता की दया याचिका का निपटारा करने के लिए 4.12.2020 और 2.5.2022 दिनांकित आदेशों के माध्यम से। यह भी पाया गया है कि गृह मंत्रालय अपनी विभिन्न शाखाओं की विभिन्न रिपोर्टों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विचार को स्थगित किया जा सकता है क्योंकि इसका प्रभाव हो सकता है -

राष्ट्र की सुरक्षा से समझौता करना या कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा करना। वर्तमान में कोई भी निर्णय लेने को स्थगित करने के सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर विचार करना इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा। यह कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर निर्णय लेना। इस प्रकार यह न्यायालय आगे कोई निर्देश जारी करना उचित नहीं समझता है। [पैरा 19] [278-ई-जी]

शत्रुघ्न चौहान और आन. V भारत संघ और अन्य। (2014) 3 एससीसी 1: [2014] 1 एस. सी. आर. 609; वी. श्रीहरण उर्फ मुरुगन बनाम। भारत संघ और अन्य। (2014) 4 एससीसी 242: [2014] 1 एससीआर 1093; नवनीत कौर बनाम।

राज्य (एन. सी. टी. ऑफ बालवांट सिंह बनाम. भारत और ओआरएस का संघ।
दिल्ली) और एएनआर। (2014) 7 एससीसी 264: [2014] 4 एससीआर 1138
प्रतिष्ठित।

कुसुमबाला तरुण दास बनाम। भारत संघ (2011) एस. सी. सी. ऑनलाइन गौ 370; हरबंस सिंह बनाम।
उत्तर प्रदेश राज्य (1982)

2 एस. सी. सी 101: [1982] 3 एस. सी. आर. 235-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2014] 1 एससीआर 609

प्रतिष्ठित

पैरा 8

[2014] 1 एससीआर 1093

प्रतिष्ठित

पैरा 8

[2014] 4 एससीआर 1138

प्रतिष्ठित

पैरा 8

[1982] 3 एससीआर 235

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

आपराधिक मूल न्यायनिर्णय: लेखन याचिका (सीआरएल)

2020 का सं. 261।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , रुपेश कुमार, सुश्री पंखुड़ी श्रीवास्तव,
सुश्री नीलम शर्मा, राजीव शर्मा, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए।

के. एम. नटराज, एएसजी, गौरव धामा एएजी, रजत नायर, सुश्री प्रियंका
दास, पीयूष बेरीवाल, दिव्यांश एच राठी, अरविंद कुमार शर्मा, वत्सल जोशी, चित्रांश शर्मा, गुरमीत सिंह
मक्कर, सुश्री मालविका राघवन, अजय पाल, सुश्री रंजीता रोहतगी, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

अनुराग सिंह, अनिल कौशिक, अनिल कुमार मिश्रा, अधिवक्ता। के लिए
हस्तक्षेपकर्ता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

विक्रम नाथ, जे।

1. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान याचिका

भारत को निम्नलिखित राहतों के लिए प्राथमिकता दी गई है:

" (क) संबंधित दया याचिका दिनांक 25.03.12 के अभिलेखों के लिए कॉल करें।

माननीय राष्ट्रपति के समक्ष दायर याचिकाकर्ता को क्षमादान देने के लिए

भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत भारत का;

(बी) उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें

उत्तरदाताओं को दी गई मौत की सजा को कम करने के लिए

अधिक की अत्यधिक देरी के कारण याचिकाकर्ता को आजीवन कारावास

कि दया याचिका पर निर्णय लेने में 08 वर्ष दिनांकित 25.03.12; [2023] 4 एस. सी.

आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ग) कोई अन्य या आगे का आदेश पारित करें जो आपके स्वामी कर सकते हैं।

न्याय के हित में उचित और उचित समझें।

2. दलीलों का आदान-प्रदान हुआ है।

3. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है और इस पर विचार किया है

अभिलेख पर सामग्री।

4. अनावश्यक विवरणों से कटा हुआ, प्रासंगिक तथ्य बताए गए हैं

इसके नीचे:

4.1 . आई. डी. 1 को हुए एक बम विस्फोट में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बेअंत सिंह और 16 अन्य लोगों की जान चली गई थी। दर्जन भर अन्य घायल हो गए। वर्तमान याचिकाकर्ता, 8 अन्य लोगों के साथ, जिन्होंने साजिश रची थी और उक्त बम विस्फोट को अंजाम दिया था,

मुकदमा चलाया गया। यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि वर्तमान याचिकाकर्ता को उक्त घटना के संबंध में 27.01.1996 पर गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालत ने दिनांक 1 के फैसले के माध्यम से याचिकाकर्ता को सह-आरोपी जगतर सिंह हवारा, गुरमीत सिंह, लखविंदर सिंह, शमशेर सिंह और नसीब सिंह के साथ दोषी ठहराया। याचिकाकर्ता को सह आरोपी जगतर सिंह हवारा के साथ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी, 302, 307 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3 (बी), 4 (बी) और 5 (बी) आर/डब्ल्यू 6 और मौत की सजा सुनाई गई। मृत्यु के संदर्भ में, उच्च न्यायालय ने दिनांकित 10.12.2010 के फैसले के माध्यम से याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की। हालाँकि, सह-अभियुक्त जगतर सिंह की दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए, इसने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। अन्य सह-अभियुक्तों ने इस न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी।

हालाँकि, वर्तमान याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले के बाद कोई अपील दायर नहीं की। याचिकाकर्ता के अनुसार, 25.03.2012 पर दया याचिका को प्राथमिकता दी गई थी। हालाँकि, प्रतिवादी भारत संघ के अनुसार, आज तक याचिकाकर्ता ने किसी भी दया याचिका को प्राथमिकता नहीं दी है। यह शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति 2 थी जिसने प्राथमिकता दी।

याचिकाकर्ता की ओर से उपरोक्त दया याचिका।

5. याचिकाकर्ता की शिकायत, जैसा कि याचिका से स्पष्ट है, यह है कि उसकी दया याचिका पर इससे अधिक के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है। 10 वर्षों तक, उसे अपनी मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

1 संक्षेप में 'आई. पी. सी.' के लिए

2 एस. जी. पी. सी. बालवंत सिंह बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [विक्रम नाथ, जे।]

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने कहा,
गृह मंत्रालय द्वारा जारी 27.09.2019 दिनांकित एक पत्र पर भरोसा किया है,

भारत सरकार ने मुख्य सचिव को संबोधित किया,

पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि 8 सिख व्यक्तियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत विशेष छूट दी जाए और जेल से रिहा किया जाए और एक कैदी (याचिकाकर्ता) की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के प्रस्ताव पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत कार्रवाई की जानी है। सभी संबंधित विभागों को इस संबंध में उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। उक्त पत्र के साथ 9 सिख कैदियों की सूची संलग्न की गई है, जिनमें से 8 को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत छूट दी गई थी और एक (याचिकाकर्ता) जिसका मामला मृत्यु के परिवर्तन के लिए विचार किया जाना था। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत आजीवन कारावास की सजा। 27.09.2019 दिनांकित पत्र को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा।

संलग्नक:

" भारत सरकार

गृह मंत्रालय

मेजर ध्यान कैंड नेशनल स्टेडियम,

महिला सुरक्षा प्रभाग, दूसरी मंजिल,

इंडिया गेट, नई दिल्ली-110,002

27 सितंबर,

2019

प्रशासक के सलाहकार,

No.227010

तिथि 10-10-2019

पीए/पी

एसएच 229010

तिथि

11/10/19

को।

सरकार की

पंजाब/गुजरात/हरियाणा/कर्नाटक/दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

उप: गुरु की 550 वीं जयंती का स्मरणोत्सव

नानक देव जी-विशेष माफी और रिहाई
कैदी।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुझे यह कहने का निर्देश दिया जाता है कि स्मरणोत्सव के अवसर पर

एक सिख कैदी की माफी और मौत की सजा हो सकती है आजीवन कारावास में परिवर्तित। इन नौ सिखों का विवरण

कैदी अनुलग्नक में दिए जाते हैं।

2. यह निर्णय लिया गया है कि 8 सिख कैदियों को विशेष छूट दी जाएगी।

संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत छूट और जेल। मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने का प्रस्ताव

भारत का संविधान। राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश संबंधित प्रशासन और मंत्रालय का केंद्र-राज्य प्रभाग

गृह मंत्रालय से इसमें सभी आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है

ध्यान दें।

3. मुझे केंद्र की सहमति से अवगत कराने का भी निर्देश दिया गया है

आठ सिख कैदियों की माफी और रिहाई (विवरण उल्लिखित) अनुलग्नक में) उन मामलों के लिए जहां अनुमोदन/सहमति /

केंद्र सरकार के साथ/के परामर्श की आवश्यकता है

लागू किसी अन्य कानून के अधीन या उसके अधीन हो सकता है। मंजूरी के साथ जारी किया जाता है।

4. यह सक्षम प्राधिकारी की

एन. सी. एल.: जैसा कि ऊपर बताया गया है

आपकी ईमानदारी

से,

एस. डी./- (अरुण

सोबती)

उप सचिव (पीआर और एटीसी),

फोन:

075297

ईमेल: डी. आर. atc@mha। गव. में

प्रतिलिपि बनाएँ:

संयुक्त सचिव (सीएस), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।

7. आठ कैदी जिन्हें के अनुसार छूट दी गई थी

निश्चित रूप से ये हैं:

((i)।

लाल सिंह @मंजीत सिंह

((ख)। देविंदर सिंह भुल्लर बलवंत सिंह बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [विक्रम नाथ, जे।]

(iii)। सुबेग सिंह

((iv)। नंद सिंह

(वी)। हरजिंदर सिंह काली

(vi)। वरयाम सिंह @साबिर @जानी

(vii)। गुरदीप सिंह खेरा

(viii)। बलबीर सिंह

याचिकाकर्ता। 8. इसके बाद विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने राज्य के विभिन्न अंगों के बीच पत्राचार की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है।

याचिकाकर्ता की मौत की सजा को कम करने के लिए। हालांकि, यह कहा जा रहा है कि आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इन परिस्थितियों में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रोहतगी ने अनुरोध किया कि चूंकि राज्य और भारत संघ 10 साल से अधिक समय से लंबित दया याचिका पर निर्णय नहीं ले पाए हैं, इसलिए यह न्यायालय स्वयं उस परिवर्तन को मंजूरी दे सकता है। श्री रोहतगी ने अपनी दलीलों के समर्थन में इस न्यायालय के निम्नलिखित तीन फैसलों पर भरोसा किया:

1. शत्रुघ्न चौहान और आन। V भारत संघ & Ors.³;

2. वी. श्रीहरण उर्फ मुरुगन बनाम भारत संघ & Ors.¹;

और

3. नवनीत कौर बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) और ए. एन. आर. 5

9. दूसरी ओर श्री अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि याचिकाकर्ता ने विशिष्ट शब्दों में अपनी बात रखी है

कि उसे इस देश की न्यायपालिका में कोई विश्वास नहीं है और उसे अपराध का हिस्सा होने का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है और उसने उच्च न्यायालय के समक्ष अवमाननापूर्ण शब्दों का उपयोग किया है जो विधिवत दर्ज किए गए हैं, वह अपने आचरण को देखते हुए किसी भी दया के योग्य नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आज तक याचिकाकर्ता ने स्वयं कोई दया याचिका प्रस्तुत नहीं की है। याचिका के साथ संलग्न दया याचिका दिनांक 25.03.2012 भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत SGPC द्वारा है। संचार.

3 (2014) 3 एससीसी 1

4 (2014) 4 एससीसी 242

5 (2014) 7 एससीसी 264 [2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऊपर उल्लिखित गृह मंत्रालय द्वारा दिनांकित 27.09.2019 केवल राज्य सरकार से भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का प्रस्ताव भेजने का अनुरोध है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार जब याचिकाकर्ता ने स्वयं कोई दया याचिका दायर नहीं की है, तो जैसा दावा किया गया है, कोई राहत देने का कोई सवाल ही नहीं है। रिलायंस को कुसुमबाला तरुण दास बनाम के मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक फैसले पर रखा गया है। भारत संघ। विद्वान ए. एस. जी. द्वारा एक अन्य आपत्ति इस आशय की है कि सह-अभियुक्त द्वारा दायर आपराधिक अपील अभी भी इस न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, क्योंकि किसी भी दया याचिका पर विचार उन अपीलों के निपटारे के बाद ही उत्पन्न होगा। दो सह-अभियुक्त लखविंदर सिंह और जगत सिंह हवारा द्वारा दायर तीन आपराधिक अपीलों और जगत सिंह हवारा की सजा को कम करने के खिलाफ सी. बी. आई. द्वारा दायर एक आपराधिक अपील का विवरण इस प्रकार है:

अपील विवरण स्थिति

एस. एल. नहीं। विशिष्टताएँ

Crl.Appeal

लं

बित है।

1

अभियुक्तों की याचिका

No.1464/2011

लखविंदर सिंह

Crl.Appeal लंबित है

2

अभियुक्तों की याचिका

No.1013/2013

जगत सिंह हवारा

3

Crl.Appeal लंबित है

सीबीआई ने दायर की याचिका

10. विद्वान ए. एस. जी. के अनुसार, इस न्यायालय के समक्ष लंबित इन अपीलों में निर्णय एक प्रासंगिक सामग्री होगी और इस पर विचार करते समय

दया याचिका का भी असर हो सकता है। इस प्रकार लंबित अपीलों के निर्णय की प्रतीक्षा करना उचित होगा। उनके निवेदन के समर्थन में, हरबंस सिंह बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया जाता है। यू. पी. 7 का राज्य

11. विद्वान ए. एस. जी. श्री नटराज ने आगे कहा कि दया याचिका पर विचार करने में कोई देरी नहीं की गई है। श्री के अनुसार

नटराज, यह 27.09.2019 के बाद ही है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने के लिए कहा

अनुच्छेद 72 के तहत मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए

6 (2011) एस. सी. सी. ऑनलाइन गौ 370 7 (1982) 2 एस. सी. सी. 101 बालवंत सिंह बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। [विक्रम नाथ, जे।]

ई संविधान। इसके बाद प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, दो

इस न्यायालय द्वारा 4.12.2020 पर आगे के निर्देश जारी करने पर कुछ निर्देश लाभ जारी किए गए थे। दोनों आदेश हैं -

नीचे लिखा है:

दिनांकित आदेश 04.12.2020:

" 27 सितंबर, 2019 के पत्र के अनुसार भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पंजाब/गुजरात/हरियाणा/कर्नाटक/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य सचिव को 550 वीं जयंती के अवसर पर पत्र लिखा है।

गुरु नानक देव जी की ओर से कैदियों की विशेष माफी और रिहाई का प्रस्ताव है। विशेष रूप से उक्त पत्र में कहा गया है:

" यह निर्णय लिया गया है कि 8 सिख कैदियों को विशेष छूट दी जाएगी।

संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत छूट और जेल से रिहा किया गया। एक कैदी की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के प्रस्ताव पर अनुच्छेद 72 के तहत कार्रवाई की जानी है।

भारत का संविधान। संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और मंत्रालय का केंद्र-राज्य प्रभाग

गृह मंत्रालय से इसमें सभी आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है

ध्यान दें "।

इस न्यायालय में सह-अभियुक्त की लंबित अपीलें। इसे अस्वीकार नहीं किया जाता है। कि याचिकाकर्ता ने स्वयं अपनी सजा के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की है। इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी अपील के परिणाम की प्रतीक्षा करने का कोई सवाल ही नहीं है। यह स्पष्ट है कि

अन्य सह-अभियुक्तों के कहने पर लंबित अपीलों के तथ्य की भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत विचार के लिए भेजे जाने वाले प्रस्ताव के साथ कोई प्रासंगिकता नहीं होगी।

श्री के. एम. नटराज, विद्वान ए. एस. जी., इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत प्रक्रिया के लिए भेजे जाने वाले 27 सितंबर, 2019 के पत्र में विचार किए गए प्रस्ताव के बारे में बयान देने के लिए समय चाहते हैं।

8 जनवरी, 2021 को मामले को सूचीबद्ध करें। "

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिनांकित आदेश 02.05.2022:

" 1. पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री की हत्या करने के लिए याचिकाकर्ता पर सह-अभियुक्त के साथ अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाया गया था। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 307/120-बी और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय

1995 का सत्र मामला संख्या 2-ए।

2. वन अपराधों के तहत दोषसिद्धि दर्ज करने के बाद, निचली अदालत ने याचिकाकर्ता और सह-आरोपी, जगतर सिंह हवारा को मौत की सजा सुनाई। 3. इसके बाद, 2007 की हत्या संदर्भ संख्या 6 के साथ-साथ सह-अभियुक्त जगतर सिंह हवारा और अन्य द्वारा 2007 की आपराधिक अपील डी. बी. पर उच्च न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 1 के फैसले के माध्यम से विचार किया गया।

4. यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता ने अपनी मौत की सजा को चुनौती नहीं दी थी और न ही उसने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील की थी।

5. उच्च न्यायालय ने सह-अभियुक्त जगतर सिंह हवारा द्वारा दायर अपील में सार पाया और मृत्यु को प्रतिस्थापित किया। आजीवन कारावास की सजा। हालाँकि, याचिकाकर्ता को दिए गए दोषसिद्धि और सजा के आदेश की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी।

6. जहाँ तक सह-अभियुक्त जगतर सिंह हवारा को दी गई दोषसिद्धि और सजा का संबंध है, उसके कहने पर 2013 की आपराधिक अपील अन्य संबंधित मामलों के साथ इस न्यायालय में विचाराधीन है। इस तरह के लंबित रहने के दौरान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंजाब, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकारों के मुख्य सचिवों को 27.09.2019 पर एक पत्र लिखा गया था।

गुरु नानक देव जी की 550 वीं जयंती के उपलक्ष्य में विशेष माफी और कैदियों की रिहाई का प्रस्ताव। 7. हम अब इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता को दी गई मौत की सजा को परिवर्तित नहीं करने में संबंधित अधिकारियों की ओर से कथित निष्क्रियता के साथ चिंतित हैं।

भारत और ओआरएस का संघ। [विक्रम नाथ, जे।]

वनाच्छादित संचार दिनांक 27.09.2019। यही कारण है कि वर्तमान रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ता द्वारा 25.03.2012 पर दी गई दया याचिका को निपटारे के लिए लिया जाए

तुरंत और उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जाए।

8. विशेष रूप से, तत्काल अपराध में अभियोजन केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा संचालित किया गया था और इस तरह, परिवर्तन और छूट के संबंध में मुद्दों पर विचार करने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा। "

यहाँ यह कहा जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता ने कभी भी किसी को पसंद नहीं किया

यह आदेश तब इस न्यायालय द्वारा 04.12.2020 पर पारित पहले के आदेश के साथ जोड़ा गया था और उसमें की गई निम्नलिखित टिप्पणियों को भी उद्धृत किया गया था: " न्यायालय द्वारा किए गए एक प्रश्न पर, श्री के. एम. नटराज, भारत संघ की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस न्यायालय में सह-अभियुक्त की लंबित अपीलें को देखते हुए प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। इसे अस्वीकार नहीं किया जाता है।

तब से जवाब में शपथ पत्र की ओर से दायर किए गए हैं उत्तरदाता नं। 1 और केंद्रीय जांच ब्यूरो (संक्षेप में "सी. बी. आई."). सी. बी. आई. के अनुसार, उसने प्रतिवादी नं. 2 द्वारा जारी डी. ओ. पत्र के जवाब में गृह सचिव को पहले ही आई. डी. 1 पर अपनी टिप्पणी भेज दी है। 1 .

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रत्यर्थी द्वारा दायर जवाब सं। 1 निम्नानुसार राज्य:

" 18. संबंधित हितधारकों से इनपुट लेने के बाद और

सीबीआई [अपराधिक अपील No.2277/2011] द्वारा दायर अपील और जगतर सिंह हवारा [अपराधिक अपील No.1013/2013] द्वारा दायर अपील को ध्यान में रखते हुए जो विचार के लिए लंबित हैं। गृह मंत्रालय में इस मामले की जांच की गई और इस प्रस्ताव को भारत के महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया।

ए। कि संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दोषी बलवंत सिंह राजोआना की ओर से दायर दया याचिकाओं पर निर्णय पर उपरोक्त दो अपीलों में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद विचार किया जा सकता है। प्रत्यर्थी सं. के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत दो बुनियादी प्रस्तुतियाँ। 1 ये निम्नानुसार हैं: I. चूंकि सह-अभियुक्त की अपील वर्तमान में लंबित है।

इस न्यायालय द्वारा विचार किए जाने पर, याचिकाकर्ता की ओर से दी गई दया याचिका तार्किक रूप से अपील के निपटारे के बाद ही विचार के लिए तैयार होगी।

जवाब में, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 का आदेश काफी स्पष्ट था और सह अभियुक्त की ओर से दायर अपील के लंबित होने के बावजूद प्रतिवादी दया याचिका पर विचार करने के लिए बाध्य थे।

II. यह प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ता ने स्वयं किसी को पसंद नहीं किया

दया याचिका, हालांकि कुछ संगठनों ने उनकी ओर से दया याचिकाओं को प्राथमिकता दी थी। जवाब में, याचिकाकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि कहा गया है कि दया याचिका ने हमेशा संबंधित का ध्यान आकर्षित किया है

अधिकारियों और अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता को संबोधित संचार से संकेत मिलता है कि ऐसी दया याचिका विचाराधीन है।

इस मुद्दे पर विचार किए बिना कि क्या याचिकाकर्ता ने स्वयं दया याचिका को प्राथमिकता दी थी, रिकॉर्ड पर संचार के साथ-साथ इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता ने तत्काल रिट याचिका को प्राथमिकता दी है, हमारे विचार में, इस द्वारा जारी निर्देशों के आलोक में मामले पर विचार करने में कोई बाधा नहीं होगी।

न्यायालय ने अपने दिनांकित 04.12.2020 आदेश में कहा। इसके अलावा, जैसा कि आदेश बालवांट सिंह V.

भारत और ओआरएस का संघ। [विक्रम नाथ, जे।]

यह स्पष्ट कर दिया था कि सह-अभियुक्त द्वारा दायर अपील के लंबित होने के बावजूद इस मामले पर विचार किया जा सकता था और किया जाना था। इन परिस्थितियों में, हम निम्नानुसार निर्देश देते हैं:

ए। इस न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 1 के आदेश में जारी निर्देश के संदर्भ में, इस मामले पर संबंधित अधिकारियों द्वारा इस तथ्य से प्रभावित हुए बिना विचार किया जाना चाहिए कि सह-अभियुक्त की ओर से दायर अपील अभी भी इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बी। निर्णय जल्द से जल्द और अधिमानतः लिया जाए।

आज से दो महीने के भीतर।

22.07.2022 पर आगे के विचार के लिए मामले को सूचीबद्ध करें।

मामला यह है कि दया याचिका पर कोई भी निर्णय लेने को स्थगित करना उचित होगा क्योंकि इसमें राष्ट्र की सुरक्षा से समझौता करने या कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा करने की गंभीर संभावना हो सकती है। 14. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान याचिका पहले से ही लिए गए निर्णय को देखते हुए खारिज की जानी चाहिए जैसा कि उन्हें सूचित किया गया था।

इस न्यायालय ने 29.09.2022 दिनांकित हलफनामे के माध्यम से।

15. न्यायालय के निर्देश पर, श्री नटराज ने गृह मंत्रालय से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जिसके परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया

दया याचिका के निपटान को स्थगित करने के लिए लिया गया जैसा कि दिनांक 29.09.2022 के हलफनामे के माध्यम से सूचित किया गया है। उक्त फाइल को न्यायालय द्वारा पढ़ा गया था।

16. यद्यपि याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने मंत्रालय की फाइल को देखने का अनुरोध किया था।

विद्वान ए. एस. जी. श्री नटराज ने गृह मामलों पर गंभीर आपत्ति जताई थी। इस न्यायालय ने यह भी आवश्यक नहीं समझा कि एक संवेदनशील मुद्दे से संबंधित उक्त फाइल को याचिकाकर्ता तक पहुँच दी जाए।

17. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों से यह भी स्पष्ट है कि दया याचिका के लंबित होने के संबंध में तर्क और

10 साल से अधिक की देरी को कायम नहीं रखा जा सकता है।

पहले, [2023] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिकाकर्ता ने स्वयं कभी कोई दया याचिका प्रस्तुत नहीं की। वर्ष 2012 की कथित दया याचिका एस. जी. पी. सी. द्वारा दायर की गई थी। इसके अलावा, गृह मंत्रालय के दिनांक 27.09.2019 के संचार के बाद, मौत की सजा को कम करने पर विचार करने का प्रस्ताव

याचिकाकर्ता शुरू किया गया था और उसी को रखने का निर्णय लिया गया था

सक्षम प्राधिकारी के अनुसार, सह-अभियुक्त के साथ-साथ सी. बी. आई. द्वारा दायर इस न्यायालय के समक्ष लंबित अपीलों के निपटारे तक लंबित प्राधिकरण, इसका असर होगा और यह कम्प्यूटेशन के उक्त प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक हो सकता है। इसके अलावा, इस न्यायालय द्वारा 04.12.2020 और 02.05.2022 पर जारी निर्देशों के बाद इस मामले पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा फिर से विचार किया गया और गृह मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे में दिए गए कारणों को देखते हुए परिवर्तन के प्रश्न को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। अतः यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि दया याचिका के निपटारे में अत्यधिक देरी हुई है।

18. हम यहां यह भी दर्ज कर सकते हैं कि श्री रोहतगी द्वारा अत्यधिक देरी के संबंध में अपने निवेदन के समर्थन में जिन तीन निर्णयों पर भरोसा किया गया था। दया याचिका का निपटान और परिणामस्वरूप इस न्यायालय द्वारा दिए गए ऐसे मामलों में परिवर्तन, याचिकाकर्ता की सहायता नहीं करता है

वर्तमान मामला। 19. पार्टियों के वकील द्वारा तर्क दिए गए किसी भी आगे के मुद्दों में गए बिना, हम पाते हैं कि इस न्यायालय द्वारा आदेशों के माध्यम से निर्देश दिए गए हैं।

दया याचिका का निपटारा करने के लिए दिनांकित 4.12.2020 और 2.5.2022

याचिकाकर्ता। हम यह भी पाते हैं कि गृह मंत्रालय अपनी विभिन्न शाखाओं की विभिन्न रिपोर्टों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विचार को स्थगित किया जा सकता है क्योंकि इसका प्रभाव राष्ट्र की सुरक्षा से समझौता करने या कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा करने से हो सकता है। यह इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा कि वह किसी भी निर्णय को स्थगित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर विचार करे। वर्तमान में निर्णय। इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर निर्णय लेना कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस प्रकार यह न्यायालय आगे कोई निर्देश जारी करना उचित नहीं समझता है।

20. याचिकाकर्ता की दया याचिका पर निर्णय को स्थगित करने का गृह मंत्रालय का रुख भी कारणों से एक निर्णय है इसके तहत दिया गया है। यह वास्तव में वर्तमान के लिए इसे देने से इनकार करने के निर्णय के बराबर है।

भारत और ओआरएस का संघ।

ए. एम. नाथ, जे.]

एड कि सक्षम प्राधिकारी, नियत ए में और जब यह आवश्यक समझा जाता है,

डी एक और निर्णय लें। उपरोक्त के अनुसार प्रस्तुत किया गया

बी.

यदि कोई हो, तो उनका निपटान किया जाता है।

लिखित याचिका का निपटारा किया गया।

नरेंद्र यादव, एलसीआरएस)